भारत तिलहन उत्पादन, प्रसंस्करण और व्यापार परिदृश्य: तथ्य और आंकड़े

रणजीत सिंह, सौम्या महापात्रा, सुमित उरहे और धृतिमान साहा

भाकृअनुप–सीफेट, लुधियाना–141004

तिलहन भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो किसानों को आवश्यक खाद्य तेल, प्रोटीन युक्त भोजन और आय प्रदान करते हैं। भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक है, जो दुनिया के खेती के क्षेत्र का 20–8 प्रतिशत हिस्सा रखता है और वैश्विक तिलहन उत्पादन में 10 प्रतिशत का योगदान देता है (तालिका 1 और 2)। प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, सोयाबीन, रेपसीड और सरसों, सूरजमुखी, कुसुम, तिल, नाइजर, अरंडी और अलसी सम्मिलित हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश प्रमुख राज्य उत्पादक हैं। सरकार राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन जैसी पहलों के माध्यम से तिलहन प्रसंस्करण का समर्थन करती है। 2023–24 के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारत का कुल तिलहन उत्पादन 365–99 लाख टन आंका गया था। वृद्धि

तालिका 1: भारत में तिलहन फसलों की स्थिति और अनुमानित क्षेत्र, उत्पादन और उपज

फसल	वर्ष 2022		
	क्षेत्रफल (मि.हे.)	उत्पादन (मि.टन)	उपज (टन / हे.)
सोयाबीन	12.50	18.75	1.50
मूंगफली	5.72	9.72	1.70
आर एंड एम	7.47	11.95	1.60
सूरजमुखी	0.97	0.87	0.90
तिल	0.27	0.22	0.80
नाइजर	1.97	1.18	0.60
छपहमत	0.32	0.16	0.50
अरंडी	1.40	2.45	1.75
अलसी	0.57	0.34	0.60
कुल	31.20	45.64	1.46

स्रोतः डीएफआई समिति का अनुमान डी,सी,नईटी से संकलित डेटा पर आधारित है

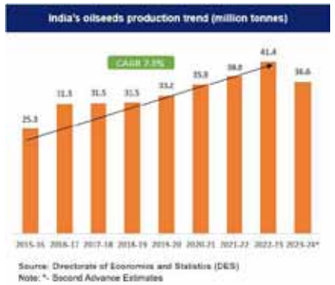

चित्र 1: भारत में तिलहन उत्पादन की प्रवृत्ति (मिलियन टन)

का यह रुझान पिछले वर्षों से जारी रहा, 2022–23 के अंतिम अनुमानों में 413–55 लाख टन का रिकॉर्ड उत्पादन दिखाया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33–92 लाख टन अधिक और पाँच साल के औसत 340–22 लाख टन से 73–33 लाख टन अधिक है। 2022–23 तक के आठ वर्षों में, तिलहन उत्पादन में 7–3 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) देखी गई, जो सरसों और रेपसीड पर विशेष कार्यक्रमों और श्रेष्ठतर प्रौद्योगिकियों के क्लस्टर प्रदर्शनों जैसी लक्षित सरकारी पहलों से प्रेरित थी। भारत में 967 वनस्पति तेल उद्योग, 54 उपकरण निर्माता, 49 तेल मिलें और रिफाइनरियां और 542 खाद्य तेल उत्पाद कंपनियाँ हैं चुनौतियों में आयात पर निर्भरता, मूल्य में उतार–चढ़ाव, जलवायु संबंधी मुद्दे और कीट शामिल हैं, जिनके लिए आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है।

भारत में सबसे बड़े तिलहन उत्पादक राज्यों

तालिका 2: खाद्य तेलों की उपलब्धता और आयात की स्थिति (मिलियन मीट्रिक टन में)

वर्ष	तिलहन उत्पादन	खाद्य तेलों की घरेलू उपलब्धता	खाद्य तेलों का आयात	कुल उपलब्धता
2017-18	31.46	10.38	14.59	24.97
2018-19	31.52	10.35	15.57	25.92
2019-20	33.22	10.65	13.42	24.07
2020-21	35.95	11.15	13.45	24.60
2021-22	37.96	11.57	14.19	25.76

स्रोतः खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त आंकड़े (http://dfpd-gov-in/oil&division-htm)

तालिका 3: भारत से तिलहनों की निर्यात स्थिति

(मात्रा मिलियन मीट्रिक टन में और मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	तिलहन		वेजिटेबल तेल		डिऑइल्ड मील	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2017-18	1.14	7573.41	0.037	566.04	3.57	7043.15
2018-19	1.03	8081.19	0.05	744.58	4.49	10557.50
2019-20	0.95	8852.31	0.074	819.15	1.92	5152.58
2020-21	1.02	9155.57	0.33	4453.1	4.36	11688.60
2021-22	0.82	8310.31	0.098	1650	2.92	7695.30

स्रोतः (http://dfpd-gov-in/oil&division-htm)

तालिका 4: भारत में वनस्पति तेल उद्योग की स्थिति (2021–22)

क्रमांक	उद्योग का प्रकार	पंजीकृत इकाइयों की संख्या
1	वनस्पति, इंट्रेस्टिफाइड वनस्पति वसा	109
2	सॉल्वेंट प्लांट और तेल मिलों के साथ रिफाइनरी	235
3	तेल मिल और मिश्रित खाद्य वनस्पति तेल मिल	493
4	सॉल्वेंट नि क f.I इकाइयाँ	130
	कुल	967

स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट (2022–23), खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार।

स्रोतः https://seaofindia-com

में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना सम्मिलित हैं। इन राज्यों में से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 2021–22 के मध्य शीर्ष उत्पादक थे, जिनकी हिस्सेदारी क्रमशः कुल उत्पादन में लगभग 23 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 16 प्रतिशत थी।

खाद्य तेलों की उपलब्धता और आयात की स्थिति

किसी विशिष्ट क्षेत्र में खाद्य तेलों की उपस्थिति स्थानीय उत्पादन, आयात, उपभोग की आदतों, कीमतों और सरकारी नियमों जैसे तत्वों के आधार पर उतार–चढ़ाव कर सकती है। 2017–22 के लिए उत्पादन, उपलब्धता और आयात के पाँच साल के रुझान और भारत से तिलहनों के निर्यात की स्थिति को नीचे तालिका 2 और तालिका 3 में दर्शाया गया है।

भारत में वनस्पति तेल उद्योग की स्थिति

भारत के वनस्पति तेल उद्योग में उच्च

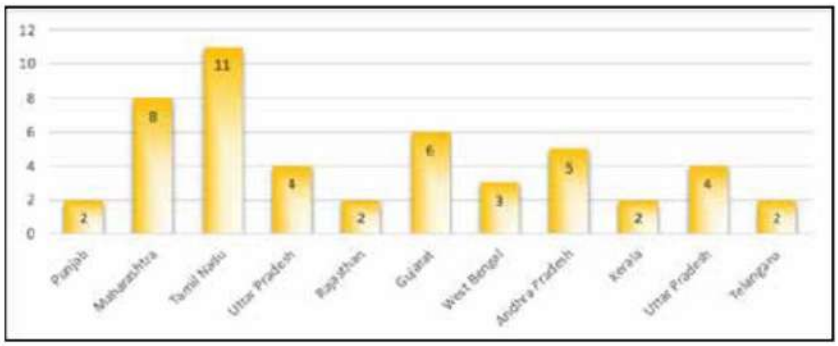

स्रोत: https://www-dnb-com/business-directory

चित्र 2 : राज्यवार तेल रिफाइनर, वनस्पति निर्माता और पैकर्स (संख्या)

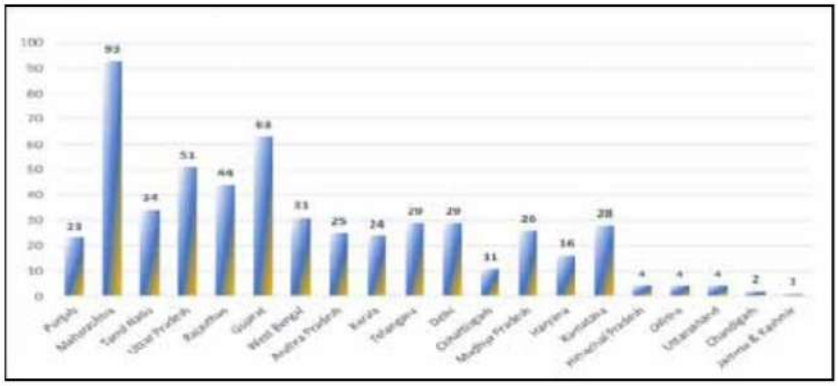

स्रोत: https://www-dnb-com/business-directory

चित्र 3 : भारत में खाद्य तेल उत्पाद कंपनियाँ (संख्याएँ)

उत्पादन और खपत की विशेषता है, जो आहार संबंधी प्राथमिकताओं से प्रभावित है, और धरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाम और सूरजमुखी तेल जैसे महत्वपूर्ण आयातों से इसे बल मिलता है। सरकार तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जैसी नीतियों के माध्यम से इस क्षेत्र का समर्थन करती है। प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धी होने और स्वास्थ्यवर्धक तेलों की ओर रुख करने के बाूद भी, उद्योग को मूल्य अस्थिरता और मौसम संबंधी अनिश्चितताओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मूल्य में उतार–चढ़ाव वैश्विक आपूर्ति–माँग में बदलाव, मुद्रा परिवर्तन और नीति समायोजन से प्रभावित होते हैं, जिससे आयात लागत और बाजार स्थिरता प्रभावित होती है। मानसून की बारिश पर निर्भरता के कारण महत्वपूर्ण मौसम संबंधी अनिश्चितता, स्थानीय उत्पादन को बाधित करती हैं, आपूर्ति को प्रभावित करती हैं और आयात बढ़ाने की आवश्यकता होती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता होती है जिसमें स्रोतों में विविधता लाना, आधारभूत ढांचे में सुधार करना और उत्तरदायी बाजार रणनीति अपनाना सम्मिलित है।

भारत में खाद्य तेल उत्पाद कंपनियाँ

भारत में कई प्रमुख खाद्य तेल उत्पाद कंपनियाँ हैं जो खाना पकाने के तेल और संबंधित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण और वितरण करती हैं। भारत में राज्यवार प्रमुख खाद्य तेल उत्पाद कंपनियों को नीचे चित्र 3 में दिखाया गया है:

निष्कर्ष

भारत का तिलहन क्षेत्र उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने और तिलहन की खेती के लिए समर्पित क्षेत्र का विस्तार करने जैसे रणनीतिक उपायों के माध्यम से उत्पादन–खपत के अंतर को पाट सकता है, संभावित रूप से ऐसे प्रोत्साहनों के माध्यम से जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और मौसमी बारिश पर निर्भरता कम करने के लिए फसल चक्र और अन्य फसलों के साथ अंतर–फसल को प्रोत्साहित करते हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्यों के माध्यम से स्थिर बाजार स्थितियों को सुनिश्चित करके, उर्वरकों जैसे आवश्यक इनपुट के लिए सब्सिडी प्रदान करके और फसल के बाद के हानि को कम करने के लिए श्रेष्ठतर भंडारण और परिवहन प्रणालियों सहित ग्रामीण कृषि आधारभूत ढांचे में निवेश करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। छोटे किसानों के खेतों के विखंडन, जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति संवेदनशीलता और बाजार की कीमतों में उतार–चढ़ाव जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने और खेती की विधियों में सुधार करने के लिए शिक्षा और विस्तार सेवाओं सहित लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, जैव ईंधन की बढ़ती वैश्विक माँग और उच्च गुणवत्ता वाले तिलहनों के निर्यात की क्षमता से लाभ उठाने के लिए काफी अवसर हैं। कृषि–तकनीक नवाचारों जैसे कि सटीक खेती, आनुवंशिक रूप से संशोधित बीज और आधुनिक सिंचाई तकनीक को अपनाने से उत्पादकता और गुणवत्ता में भारी वृद्धि हो सकती है। विशेष रूप से महिलाओं की ओर से अधिक समावेशी भागीदारी को प्रोत्साहित करके, अनुकूलित प्रशिक्षण और ऋण तक पहुंच के माध्यम से इस क्षेत्र को और सुदृढ़ किया जा सकता है। इन बहुआयामी प्रयासों के माध्यम से, भारत अपने तिलहन उद्योग को एक मजबूत, आत्मनिर्भर क्षेत्र में बदल सकता है, आयात निर्भरता को कम कर सकता है और अपने कृषि समुदायों के लिए आर्थिक स्थिरता बढ़ा सकता है।